



माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर (छ.ग.)

दाण्डिक अपील संख्या – 100/2006

एकल पीठ :

माननीय श्री दिलीप रावसाहेब देशमुख न्यायाधीश

सुखलाल

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य

आदेश हेतु आज ही नियत करें

-



सही/-

श्री दिलीप रावसाहेब देशमुख

न्यायाधीश



माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर (छ.ग.)

दाण्डिक अपील संख्या – 100/2006

एकल पीठ :

माननीय श्री दिलीप रावसाहेब देशमुख न्यायाधीश

सुखलाल

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य

उपस्थित :-

श्री शैलेन्द्र दुबे, अभियुक्त-अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता

श्री सुमेश बजाज, शासकीय अधिवक्ता/अतिरिक्त, लोक अभियोजक राज्य हेतु

आदेश

(दिनांक 06-04-2006)

1- यह अपील, सत्र प्रकरण क्रमांक 116/2005 में श्री ए.के. प्रधान, विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, सक्ती, जिला बिलासपुर द्वारा दिनांक 10-01-2006 को दिए गए निर्णय के विरुद्ध है, जिसके तहत अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के तहत दोषी ठहराया गया था और उसे 5 वर्ष के कठोर कारावास और 5,000/- रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया और अदा न करने पर 5 माह के अतिरिक्त कठोर कारावास का दंड भुगतना होगा।

2- मामले का तथ्यात्मक सार यह है कि 03-05-2004 को अपीलकर्ता अपनी लगभग 11 वर्षीय बेटी के साथ ग्राम-तुषार, थाना जैजैपुर, जिला जांजगीर चांपा स्थित किराना दुकान पर मौजूद था। लगभग 11 वर्षीय बालक अजय कुमार चंद्रा अभि.सा.-1 सुबह लगभग 05:45 बजे 250 ग्राम चीनी खरीदने वहाँ आया। अपीलकर्ता ने 4.50 रुपये मूल्य की चीनी तोलकर अजय कुमार अभि.सा.-1 को दे दी, जिसने अपीलकर्ता को 5 रुपये का भुगतान किया। चूँकि अपीलकर्ता के पास खुले पैसे नहीं थे, इसलिए अजय कुमार ने गुटखा का पाउच माँगा।

इस पर, अपीलकर्ता अचानक क्रोधित हो गया, उसने अजय कुमार को जमीन पर धकेल दिया और 5 किलोग्राम का लोहे का वजन (बाट) उठाकर उसके दाहिने कान के पास और सिर के बाईं ओर मारा। अजय कुमार चंद्र बेहोश हो गया।

3- खुबराम चंद्रा अभि.सा.-2, दादा और मन कुमारी अभि.सा.-3, अजय कुमार चंद्रा की बहन, भरतीन बाई अभि.सा.-4, सावित्री बाई अभि.सा.-5, अपीलकर्ता की माँ चीख-पुकार सुनकर इकट्ठा हुईं। खुबराम चंद्रा अभि.सा.-2 ने तुरंत घटनास्थल से लगभग 5 किलोमीटर दूर स्थित पुलिस थाना - जैजैपुर में एफआईआर दर्ज कराई। डॉ. के.एल. उरांव, चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जैजैपुर, अभि.सा.-6 ने उसी दिन सुबह



7:45 बजे अजय कुमार की जाँच की और पाया कि वह अर्ध-चेतन अवस्था में है और उसे उल्टी भी हो रही है। उन्होंने निम्नलिखित **चोट** पाया –

- (ए) दाहिने बाहरी कान के मध्य में 6"×1" का एक लम्बा घाव, मुंह के दाहिने कोण से 1" दूर, दाहिने बाहरी कान के मध्य में कठोर और कुंद वस्तु के कारण हुआ घाव और रक्तस्राव।
- (बी) कठोर और कुंद वस्तु के कारण खोपड़ी के बाएं पोस्टोपैरिएटल क्षेत्र पर 1 1/2"×1/2"×1/2" रक्तस्राव के साथ खोपड़ी की हड्डी में गहरा एक घाव।

4- अजय कुमार चंद्रा अभि.सा.-1 को जिला अस्पताल, जांजगीर-चांपा के विशेषज्ञ की राय के लिए शल्य चिकित्सा विशेषज्ञ और ईएनटी विशेषज्ञ के पास भेजा गया, डॉ. केएल उरांव अभि.सा.-6 ने कहा कि मामले को तत्काल आगे के प्रबंधन की आवश्यकता है।

5- अजय कुमार चंद्रा अभि.सा.-1 को बेहोशी की हालत में दोपहर 02:05 बजे खुबुराम चंद्रा अभि.सा.-2 द्वारा छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान, बिलासपुर (सी.आई.एम.एस.) में स्थानांतरित किया गया। उन्हें तुरंत जीवन रक्षक दवाएं और आई.वी. द्रव दिया गया और उपचार दिया गया। 03-05-2004 को अजय कुमार चंद्रा को होश नहीं आया और उन्हें 04-05-2004 को ऐंठन के साथ 3 से 4 बार उल्टी हुई, सिर का सी.टी. स्कैन किया गया जिसमें रिपोर्ट एक्स. पी-19(ए) सेरेब्रल पैरेन्काइमा का पता चला, जिसमें बाएं पार्श्विका में ऊपर की ओर छोटा एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमेटोमा दिखाई दे रहा था। 06-05-2004 तक अजय कुमार चंद्रा को होश नहीं आया और वे बेचैन रहे। वह 07-05-2004 और 08-05-2004 को अर्ध-चेतन में था, लेकिन 09-05-2004 को पहली बार **होश आया**, अजय कुमार चंद्रा को होश आया और यह स्वास्थ्य स्थिति 12 और 13-05-2004 तक जारी रही। 13-05-2004 को अजय कुमार चंद्रा को अनुरोध पर अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। छुट्टी मिलने पर, चोट का इतिहास 03-05-2004 को **बाट** द्वारा हमले के कारण सिर में चोट के रूप में दिया गया था। घटना की तारीख को अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत किए जाने पर **प्रदर्श** पी-14 के तहत 5 किलोग्राम का लोहे का वजन जब्त किया गया था। 03-05-2004 को **प्रदर्श** पी-13 के तहत घटनास्थल से सादी मिट्टी और खून से सनी मिट्टी भी जब्त की गई और जांच के लिए फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, रायपुर को भेज दी गई। दिनांक 30-10-2004 की रिपोर्ट के अनुसार लोहे पर खून की उपस्थिति, 5 किलोग्राम वजन, आर्टिकल-सी और खून से सनी मिट्टी की पुष्टि हुई।

6- एक प्रश्न के उत्तर में, डॉ. के.एल. उरांव, अभि. 6 ने प्र. 5 के माध्यम से अपनी राय दी कि अजय कुमार चंद्रा को लगी चोट अपीलकर्ता से जब्त किए गए लोहे के वजन से **आ** सकती है। उन्होंने आगे कहा कि यदि तत्काल उपचार नहीं दिया जाता, तो अजय कुमार चंद्रा की मृत्यु संभव थी। जाँच पूरी होने के बाद, अपीलकर्ता पर भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के तहत मुकदमा चलाया गया। अपीलकर्ता ने अपना अपराध अस्वीकार करते हुए **तर्क** दी कि घटना के समय उसका मानसिक संतुलन असंतुलित था। अभियोजन पक्ष ने 13 गवाहों का **परीक्षण किया**। बचाव पक्ष की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। विद्वान न्यायाधीश ने अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर अपीलकर्ता को दोषी ठहराया और पैरा 1 में उल्लिखित अनुसार **दंडित किया**।

7- अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री शैलेन्द्र दुबे ने तर्क दिया कि घटना के दिन अपीलकर्ता की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। उन्होंने डॉ. बी.आर. अम्बेडकर मेमोरियल हॉस्पिटल, रायपुर के मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष द्वारा दिनांक 25-02-2005 को भेजी गई रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि 07-02-



2005 को मनोरोग वार्ड में भर्ती अपीलकर्ता की विस्तृत जाँच और वार्ड के व्यवहार के अवलोकन के बाद उसे मनोविकृति से पीड़ित पाया गया था। अजय कुमार चंद्रा, अभि.सा.-1, मान कुमारी, अभि.सा.-3 और सावित्री बाई, अभि.सा.-5 की गवाही का हवाला देते हुए तर्क दिया गया कि घटना के 5-6 वर्ष पूर्व से अपीलकर्ता की मानसिक स्थिति सामान्य नहीं थी। इसलिए यह तर्क दिया गया कि चूंकि अपीलकर्ता घटना के समय मानसिक रूप से अस्वस्थ होने के कारण कृत्य की प्रकृति को जानने में असमर्थ था या वह जो कर रहा है वह गलत है या **विधि** के विपरीत है, इसलिए वह **भा.द.वि.** की धारा 84 के लाभ का हकदार था।

8- यह भी तर्क दिया गया कि अभियोजन पक्ष ने अजय कुमार चंद्रा पर लोहे के वजन से हमला करने की अपीलकर्ता की कोई आपराधिक **मनःस्थिति** नहीं थी। इससे यह भी पता चला कि घटना के समय अपीलकर्ता मानसिक रूप से अस्वस्थ था। अभियोजन पक्ष ने यह साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं दिया कि अपीलकर्ता ने अजय कुमार चंद्रा पर लोहे के वजन से हमला किया था। वैकल्पिक रूप से, यह भी तर्क दिया गया कि अजय कुमार को लगी चोटें गंभीर नहीं थीं क्योंकि वे **भा.द.वि.** की धारा 320 के किसी भी **मानदंड** के अंतर्गत नहीं आती थीं और इसलिए अपीलकर्ता द्वारा किया गया कोई भी अपराध **भा.द.वि.** की धारा 324 से आगे **जा सकता** था। अपीलकर्ता की मानसिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, विद्वान **अधिवक्ता** ने तर्क दिया कि अपीलकर्ता को **दिए गए दंड** को उसके द्वारा पहले ही **भुगतें गये दंड तक** में घटा दिया जाना चाहिए।

9- दूसरी ओर, विद्वान **“आसकीय अधिवक्ता** श्री सुमेश बजाज ने आरोपित निर्णय के समर्थन में तर्क दिया। उन्होंने तर्क दिया कि अपराध के समय पागलपन या मानसिक विकृति साबित करने का भार पूरी तरह से अभियुक्त पर था। अभियुक्त द्वारा यह साबित करने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया कि अपराध के समय वह मानसिक विकृति से ग्रस्त था जिसे **विधि के तहत** पागलपन कहा जा सके और जो उसे आपराधिक दायित्व से मुक्त कर सके। यह तर्क दिया गया कि मानसिक विकृति का गठन करने के लिए ताकि कृत्य को भारतीय दंड संहिता की धारा-84 के दायरे में लाया जा सके, यह दर्शाया जाना चाहिए कि मानसिक विकृति ऐसी थी कि व्यक्ति कृत्य की प्रकृति को जानने में असमर्थ था या वह जो कर रहा है वह गलत है या **विधि** के विपरीत है। ए.आई.आर. - 1974- सुप्रीम कोर्ट 216 में रिपोर्ट किए गए ओयामी अयातु बनाम मध्य प्रदेश राज्य पर भरोसा करते हुए, यह भी तर्क दिया गया कि केवल तथ्य यह है कि अजय कुमार अभि.सा.-1 या खुबूराम चंद्र अभि.सा.-2 ने अपीलकर्ता द्वारा अजय कुमार चंद्र अभि.सा.-1 पर लोहे के वजन से हमला करने के किसी भी **आशय** या मनःस्थिति का खुलासा नहीं किया, जिससे स्वतः यह पता नहीं चलता कि अपीलकर्ता विकृत दिमाग का था। ए.आई.आर. 2004 सुप्रीम कोर्ट 1264 में रिपोर्ट किए गए धूल सिंह बनाम राजस्थान राज्य पर भी भरोसा किया गया, यह तर्क देते हुए कि मौत का कारण बनने का **आशय** शरीर के उस हिस्से से पता लगाया जा सकता है जहां भारी वार किए गए थे, अपराध का हथियार यानी 5 किलोग्राम का एक बहुत भारी लोहे का वजन (**बाट**) चोट पहुंचाने में इस्तेमाल किया गया, जिस बल से चोटें पहुंचाई गईं और अजय कुमार चंद्र को **जिस बाट चोटे पहुंचाई गईं**।

10- अंत में विकल्प के रूप में यह तर्क दिया गया कि 11 साल के नाबालिग लड़के पर 5 किलो के भारी लोहे के वजन से महत्वपूर्ण हिस्सों पर हमला किया गया था, यानी दाहिने बाहरी कान के पास और खोपड़ी के बाएं पोस्टोपैरिएटल क्षेत्र पर, सी.टी. स्कैन रिपोर्ट और **सिम्स** के बेड हेड टिकट और डॉ. के.एल. उरांव, अभि.सा.-6 की राय से पता चला कि अजय कुमार चंद्रा का जीवन छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान में उचित समय पर दिए गए उपचार के बिना नहीं बचाया जा सकता था। इस प्रकार अजय कुमार चंद्रा को ऐसी चोटें आईं जो जीवन के लिए खतरनाक थीं, जिससे **भा.द.वि.** की धारा 320 की धारा-8 लागू होती है और इस प्रकार यह एक गंभीर चोट



है। अपीलकर्ता द्वारा किया गया अपराध किसी भी मामले में **भा.द.वि.** की धारा 326 के अंतर्गत नहीं आता। **स्पेशल** कोर्ट द्वारा दिए गए 5,000/- के जुर्माने में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं थी।

- 11- प्रतिद्वंदी तर्कों को सुनने के बाद, मैंने अभिलेख का अवलोकन किया है। पहला प्रश्न जिस पर विचार करने की आवश्यकता है, वह यह है कि क्या अपीलकर्ता घटना की तिथि और समय पर मानसिक रूप से अस्वस्थ था। भारतीय दंड संहिता की धारा 84 इस प्रकार है:-

विकृत चित्त वाले व्यक्ति का कार्य कोई भी बात अपराध नहीं है जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है जो कार्य करते समय विकृत चित्त के कारण कार्य की प्रकृति को जानने में असमर्थ है या यह जानने में असमर्थ है कि वह ऐसा कार्य कर रहा है जो गलत है या विधि के प्रतिकूल है। धारा-84

यह सर्वविदित है कि **विकृत चित्त** का आकलन करने के लिए महत्वपूर्ण समय वह समय होता है जब अपराध वास्तव में किया जाता है। धारा 84 में प्रदत्त छूट का हकदार होने के लिए यह साबित करने का भार अभियुक्त पर है कि अपराध के समय अपीलकर्ता मानसिक रूप से विकृत था। यह मानसिक विकृति ही होनी चाहिए जो अभियुक्त को आपराधिक दायित्व से मुक्त करती है। अपराध के समय **विकृत चित्त** का गठन करने के लिए, अभियोजन पक्ष को यह साबित करना होगा कि अपराध के समय अपराधी अपने कृत्य की प्रकृति को जानने में असमर्थ था या वह ऐसा कार्य कर रहा है जो या तो गलत है या **विधि** के विरुद्ध है। यह भी समझना आवश्यक है कि चिकित्सीय दृष्टिकोण से चिकित्सीय **विकृत विक्षिप्ता** को मानसिक **विक्षिप्ता** से अलग किया जाना चाहिए, इसका अर्थ **भा.द.वि.** की धारा 84 के तहत छूट का दावा करने के लिए हमेशा **विधिक विक्षिप्ता** नहीं होगा। यह भी सुस्थापित है कि **विक्षिप्ता** व्यक्तिगत बचाव नहीं है, इसे साबित करना होगा। **विक्षिप्ता** का बचाव केवल अपराध के चरित्र से प्राप्त तर्कों पर स्वीकार नहीं किया जा सकता है। अपराध के समय केवल मानसिक विकार के अभाव से भी मानसिक अस्वस्थता का प्रमाण नहीं दिया जा सकता है। इसे अपराध से पहले और बाद के आचरण से तय किया जाना चाहिए। ओयामी अयातु बनाम मध्य प्रदेश राज्य में एआईआर 1974 सुप्रीम कोर्ट 216 में रिपोर्ट किया गया, यह माना गया कि केवल तथ्य यह है कि मृत्यु एक तुच्छ मामले पर हुई थी, यह निष्कर्ष भी नहीं निकालेगा कि अपीलकर्ता एक स्वस्थ **चित्त** व्यक्ति नहीं था।

- 12- दह्याभाई छगनभाई ठक्कर बनाम गुजरात राज्य, ए.आई.आर. 1964-एस.सी.-1563 में **प्रकाशित** मामले में, यह माना गया कि जब **विधिक विक्षिप्ता का तर्क दिया जाता है**, तो न्यायालय को यह विचार करना होता है कि क्या अपराध के समय अभियुक्त मानसिक विकृति के कारण कृत्य की प्रकृति को जानने में असमर्थ था या वह ऐसा कुछ कर रहा है जो या तो गलत है या **विधि** के विरुद्ध है। अभियुक्त की मानसिक स्थिति का पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण समय वह समय है जब अपराध किया गया था। क्या अभियुक्त ऐसी मानसिक स्थिति में था कि वह भारतीय दंड संहिता की धारा 84 के लाभ का हकदार हो, यह केवल उन परिस्थितियों से ही स्थापित किया जा सकता है जो अपराध से पहले, उसके दौरान और बाद में घटित हुईं।

- 13- दह्याभाई (सुप्रा) में आगे यह माना गया कि **विक्षिप्ता के तर्क** के विरोध में सबूत के **भार** के सिद्धांत को निम्नलिखित प्रस्तावों में कहा जा सकता है: (1) अभियोजन पक्ष को **युक्तियुक्त** संदेह से परे साबित करना होगा कि अभियुक्त ने अपेक्षित मनःस्थिति के साथ अपराध किया था और यह साबित करने का **भार** हमेशा **विचारण** के शुरु से अंत तक अभियोजन पक्ष पर रहता है। (2) यह खंडित करने योग्य उपधारणा है कि अभियुक्त **विक्षिप्त** नहीं था, जब उसने अपराध किया था, भारतीय दंड संहिता की धारा 84 में दिए गए अर्थों में अभियुक्त न्यायालय के समक्ष सभी **सुसंगत** साक्ष्य, चाहे वे वास्तविक, दस्तावेजी या परिस्थितिजन्य हों, प्रस्तुत करके इसका खंडन कर सकता है, लेकिन उस पर सबूत का भार सिविल कार्यवाही में पक्षकार के भार से अधिक नहीं है। (3) यहां



तक कि यदि अभियुक्त निर्णायक रूप से यह स्थापित करने में सक्षम नहीं था कि वह अपराध करते समय पागल था, तो अभियुक्त या अभियोजन पक्ष द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य न्यायालय के मन में अपराध के एक या अधिक अवयवों के संबंध में **युक्तियुक्त संदेह** उत्पन्न कर सकता है, जिसमें अभियुक्त की मानसिक **स्थिति** भी शामिल है और उस स्थिति में न्यायालय अभियुक्त को इस आधार पर दोषमुक्त करने का हकदार होगा कि अभियोजन पक्ष पर निहित सबूत के सामान्य भार का निर्वहन नहीं किया गया।

14- रतनलाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य, एआईआर 1971, सर्वोच्च न्यायालय-778 में प्रकाशित, में यह माना गया कि मानसिक विकृतियों को सिद्ध करने के लिए निर्णायक समय वह होता है जब अपराध वास्तव में किया जाता है। इसे सिद्ध करने का भार अभियुक्त पर उन परिस्थितियों के आधार पर डाला जा सकता है जो अपराध से पहले, उसके साथ और उसके बाद घटित हुईं। इस मामले में बचाव पक्ष ने यह दर्शाने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत किए कि अभियुक्त की मानसिक स्थिति ऐसी थी कि अगर वह बैठा रहता, तो बैठा रहता, अगर जाना चाहता, तो जाता और अगर नदी में गिरना चाहता, तो गिर जाता। उसकी मानसिक स्थिति ऐसी थी कि वह अपने कपड़ों और घर में आग लगा लेता था। यह भी दर्शाया गया कि नेमीचंद के खलियान में आग लगाने के अपराध के बाद, जब अभियुक्त से पूछा गया, तो उसने कहा, "मैंने इसे जला दिया है और तुम जो चाहो करो।" उस मामले में अपीलकर्ता ने किसी को भी अपने घर में प्रवेश नहीं करने दिया और घर पर ताला लगा दिया और उसके बच्चे अपना खाना बाहर खाते थे और अभियुक्त किसी से बात नहीं करता था। समग्र स्थिति को ध्यान में रखते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि घटना के समय अपीलकर्ता भारतीय दंड संहिता की धारा 84 के अर्थ के अंतर्गत **विक्षिप्त** था।

15- वर्तमान मामले में, यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं है कि घटना की तारीख से पहले आरोपी अपीलकर्ता का व्यवहार **अयुक्तियुक्त** था। यह आरोप कि वह किसी के भी घर में घुस जाता था और किसी भी व्यक्ति को गाली देना शुरू कर देता था, अजय कुमार **अ.सा.-1** द्वारा स्पष्ट रूप से नकार दिया गया था। इस संबंध में बचाव पक्ष द्वारा कोई सबूत नहीं दिया गया। यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है कि अजय कुमार पर हमला करने के बाद, आरोपी ने अपने कपड़े फाड़ने शुरू कर दिए या रोना शुरू कर दिया या **अयुक्तियुक्त** तरीके से व्यवहार किया या भावशून्य **ता** भाव के साथ चुप रहा और सवालियों का जवाब नहीं दिया। दूसरी ओर, सबूत दिखाते हैं कि आरोपी अपनी बेटी के साथ अपनी किराने की दुकान में बैठा था और सामान्य व्यवहार कर रहा था। पैराग्राफ -3 में मन कुमारी **अ.सा.-3** की गवाही भी दिखाती है कि अपीलकर्ता तर्कसंगत और सामान्य रूप से बात कर रहा था। अपीलकर्ता ने चीनी का वजन किया था और इसे प्लास्टिक की पन्नी में अजय कुमार को सौंप दिया था। इस प्रकार, रिकॉर्ड पर यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं है कि अभियुक्त ने घटना के समय या बाद में **अयुक्तियुक्त** तरीके से व्यवहार किया था। इसलिए, केवल इस तथ्य से कि गवाह ने स्वीकार किया कि अभियुक्त अपनी मानसिक स्थिति के लिए उपचार करा रहा था, अपने आप में यह नहीं दिखाएगा कि अभियुक्त-अपीलकर्ता घटना के समय मानसिक रूप से अस्वस्थ था जैसा कि **भा.द.वि.** की धारा-84 के तहत आवश्यक है। बचाव पक्ष द्वारा यह भी आग्रह किया गया था कि अजय कुमार और अपीलकर्ता के परिवार के बीच सामान्य संबंध थे। इसे प्रमाणित करने के लिए पैरा-4 में अजय कुमार के बयानों खुबूराम चंद्र **अ.सा.-2** और मान कुमारी **अ.सा.-3** का हवाला दिया गया। हालांकि, जैसा भी हो, यह अपने आप में यह नहीं दिखाता कि अपीलकर्ता अपराध के समय मानसिक रूप से अस्वस्थ था।

16- अभिलेख के अवलोकन से पता चलता है कि 17-09-2004 को अभियुक्त अपीलार्थी ने विचारण न्यायाधीश के समक्ष आवेदन दिया था कि वह 5 से 6 वर्षों से मानसिक रूप से विक्षिप्त है, इसलिए उसके विरुद्ध



दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 328 के अनुसार कार्यवाही की जाए। इस आवेदन के अनुसरण में, विचारण न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश पर, अपीलार्थी को 07-02-2005 को डॉ. बी.आर. अंबेडकर अस्पताल रायपुर के मनोचिकित्सा वार्ड में भर्ती कराया गया था। विस्तृत जांच और वार्ड व्यवहार के अवलोकन के बाद उसे मनोविकृति से पीड़ित पाया गया। यह राय दी गई कि उपचार से अपीलार्थी की स्थिति में सुधार हुआ है और उसे आगे अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता नहीं है। यह भी राय दी गई कि इस निर्णय को सामान्य पाया गया और वह कानूनी कार्यवाही को समझ सकता है। ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होने पर, अभियुक्त अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने दिनांक 17-09-2004 के आवेदन पर यह पुष्टि की थी कि वह मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर **द.प्र. संहिता** की धारा 328 के तहत दायर आवेदन पर जोर नहीं देते। एक तरह से, यह इस तर्क को छोड़ने के समान है कि अपीलकर्ता घटना की तारीख को मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति था। अपीलकर्ता द्वारा दायर किए गए उपचार पत्र किसी भी साक्ष्य द्वारा सिद्ध नहीं किए गए।

17- अजय कुमार चंद्र **अ.सा.-1** ने कहा है कि लगभग 6 बजे वह अपीलकर्ता की दुकान से चीनी खरीदने गया था। उसने जिरह में स्वीकार किया कि रूपा बाई, अपीलकर्ता की बेटी जो उसकी उम्र की थी, दुकान में अपीलकर्ता के साथ मौजूद थी। जिरह में बचाव पक्ष द्वारा यह भी कहा गया कि अपीलकर्ता की दुकान से 5 किलोग्राम वजन जब्त करने की बात लालजी शुभम **अ.सा.-9** की पूरी तरह से अखंडित गवाही से साबित होती है, जिसने साक्ष्य के दौरान **प्रदर्श पी-14** के माध्यम से जब्ती ज्ञापन साबित कर दिया है। लोहे के वजन को भी रासायनिक परीक्षण के लिए **न्यायालयीन** विज्ञान प्रयोगशाला में भेजा गया था और **न्यायालयीन** विज्ञान प्रयोगशाला द्वारा खून की उपस्थिति की पुष्टि की गई थी। **खुबूराम चंद्र अ.सा.-2** ने स्पष्ट रूप से कहा है कि शोर सुनकर जब वह मौके पर पहुंचा, तो उसने देखा कि अजय कुमार अपीलकर्ता की दुकान के पास जमीन पर पड़ा था **सिम्स** द्वारा अजय कुमार चंद्रा के मेडिकल परीक्षण के कागजात में भी लोहे के वजन से हमले का इतिहास दर्ज है। बचाव पक्ष ने ऐसा कोई तर्क नहीं दिया है कि अजय कुमार को किसी अन्य प्रकार से चोट लगी है। इस प्रकार यह स्थापित होता है कि चीनी देने के बाद जब अजय कुमार ने अपीलकर्ता से बॉम्बे गुटखा पाउच मांगा, तो अपीलकर्ता ने उसे जमीन पर धकेल दिया और उसके शरीर के महत्वपूर्ण अंगों पर 5 किलो के भारी लोहे के वजन से बार-बार प्रहार किया।

18- डॉ. के.एल. उरांव **अ.सा.-6**, जिन्होंने 03-05-2004 को अजय कुमार चंद्रा की चिकित्सीय जांच की थी, ने कहा कि उन्होंने मुंह के दाहिने कोण से 1 इंच की दूरी पर दाहिने बाहरी कान के बीच में 6"×1" का एक लंबा चोट का निशान देखा और खोपड़ी के बाएं पोस्टोपैरिएटल क्षेत्र पर 1½"×1½"×½ रक्तस्राव के साथ खोपड़ी की हड्डी तक गहरा एक घाव देखा। अजय कुमार अर्धचेतन अवस्था में थे और उन्हें जांजगीर-चांपा एक्स. पी-20 के बीडीएम अस्पताल में रेफर किया गया था **प्रदर्श पी-20**। **सिम्स** में अजय कुमार को मिले उपचार के इन्डोर कागजात स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि जीवन रक्षक दवाओं और सर्वोत्तम चिकित्सा उपचार के बावजूद, अजय कुमार को 09-05-2004 को ही होश आया। इससे यह भी पता चलता है कि अजय को नाक से खून आने और उल्टी होने का इतिहास था और वह चिड़चिड़ा था। यदि घटना के 6 घंटे के भीतर उचित चिकित्सा उपचार नहीं मिलता तो मृत्यु संभव थी।

19- हालांकि अभियोजन पक्ष ने अभियुक्त-अपीलकर्ता द्वारा अजय कुमार के सिर और कान पर 5 किलोग्राम के भारी लोहे के वजन से हिंसक प्रहार करके उसकी जान लेने के प्रयास का कोई आपराधिक कारण स्थापित नहीं किया है, फिर भी **खूबराम चंद्र**। **अभि.सा.-2** के **प्रतिपरीक्षण कड़िका-4** में कुछ संकेत हैं, जिन्होंने बचाव पक्ष द्वारा विशेष रूप से पूछे जाने पर इस बात से इनकार किया कि उन्होंने अजय कुमार को केवल 1/- रुपये के साथ



चीनी खरीदने के लिए भेजा था। इस संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है कि 4.50 रुपये की चीनी तौलने और देने के बाद जब अजय कुमार ने अपीलकर्ता को केवल 1/- रुपये दिए और बॉम्बे गुटखा पाउच भी मांगा, तो इससे अपीलकर्ता नाराज हो गया और उसने अजय कुमार को जमीन पर धकेलने के बाद, अजय कुमार के दाहिने कान और सिर के बाईं ओर बहुत भारी लोहे के वजन से हमला किया।

20- अपीलकर्ता ने एलकारी शंकरा बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, खंड-VIII 1989(2) अपराध पृष्ठ संख्या 702, सन्ना एरोना बनाम कर्नाटक राज्य, 1983 Cr.L.J. 619 और शमा टुडू बनाम राज्य, 1987 Cr.L.J. 618 पर भरोसा करते हुए तर्क दिया है कि **आपराधिक मनःस्थिति** का अभाव यह इंगित करने के लिए एक मजबूत परिस्थिति होगी कि अपीलकर्ता अपराध के समय **विकृतचित्त** दिमाग का था। हालांकि, बचाव पक्ष द्वारा उद्धृत मामलों के तथ्य और परिस्थितियां स्पष्ट रूप से अलग-अलग हैं क्योंकि उन मामलों में अपराध के समय और बाद में अभियुक्त-अपीलकर्ता के **अयुक्तियुक्त** व्यवहार को समझाया गया था। वर्तमान मामले में ऐसी कोई स्थिति नहीं है। अजय कुमार द्वारा माँगी गई चीनी देने तक अपीलकर्ता पूरी तरह से **युक्तियुक्त** व्यक्ति की तरह व्यवहार करता रहा। अजय कुमार पर हमला करने के बाद भी, अपीलकर्ता का व्यवहार **अयुक्तियुक्त** नहीं दिखाया गया है। केवल यह तथ्य कि वह मानसिक बीमारी का इलाज करा रहा था, अपने आप में यह नहीं दर्शाता कि घटना के समय अभियुक्त मानसिक रूप से अस्वस्थ था, जैसा कि **भा.द.वि.** की धारा 84 के तहत माना जाता है।

21- हरि मोहन मंडल बनाम झारखंड राज्य मामले में, जिसकी रिपोर्ट एआईआर 2004 सुप्रीम कोर्ट 3687 में दी गई है, यह अभिनिर्धारित किया गया कि **भा.द.वि.** की धारा 307 के तहत दोषसिद्धि को उचित ठहराने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि मृत्यु का कारण बनने वाली शारीरिक चोट पहुँचाई गई हो। यद्यपि वास्तव में पहुँचाई गई चोट की प्रकृति अक्सर अभियुक्त के **आशय** के बारे में निष्कर्ष निकालने में काफ़ी मददगार साबित हो सकती है, फिर भी इस **आशय** का अनुमान अन्य परिस्थितियों से भी लगाया जा सकता है और कुछ मामलों में तो वास्तविक चोटों के संदर्भ के बिना भी इसका पता लगाया जा सकता है। यह धारा अभियुक्त के कार्य और उसके परिणाम के बीच अंतर करती है, हालाँकि जहाँ तक हमला किए गए व्यक्ति का संबंध है, ऐसे किसी कार्य का कोई परिणाम नहीं हो सकता है, फिर भी ऐसे मामले हो सकते हैं जिनमें अपराधी इस धारा के तहत उत्तरदायी होगा। यह आवश्यक नहीं है कि हमले के शिकार व्यक्ति को वास्तव में पहुँचाई गई चोट सामान्य परिस्थितियों में हमला किए गए व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त हो। न्यायालय को यह देखना होगा कि क्या कार्य, चाहे उसका परिणाम कुछ भी हो, धारा में उल्लिखित **आशय** या ज्ञान और परिस्थितियों में किया गया था। किसी अपराध को अपराधी बनाने के लिए प्रयास का अंतिम से पहले का कृत्य होना ज़रूरी नहीं है। **विधि** में यह पर्याप्त है कि तीनों के निष्पादन में किसी प्रत्यक्ष कृत्य के साथ कोई आशय भी मौजूद हो।

22- धूल सिंह बनाम राजस्थान राज्य, ए.आई.आर. 2004 एस.सी. 1264 में दर्ज मामले पर भरोसा करते हुए, मेरी यह सुविचारित राय है कि अपीलकर्ता का **आशय** इस्तेमाल किए गए अपराध के हथियार (5 किलोग्राम का एक बहुत भारी लोहे का भार), घायल 11 वर्षीय बालक की कोमल आयु, शरीर के उन महत्वपूर्ण अंगों पर जहाँ अपराध के हथियार से हिंसक और बार-बार प्रहार किया गया था, और अजय कुमार को लगी चोटों की प्रकृति से पता लगाया जा सकता है, जिससे इस बात में कोई संदेह नहीं रह जाता कि घटना के समय अपीलकर्ता का **आशय** अजय कुमार की हत्या करना था। केवल यह तथ्य कि कोई आपराधिक मनःस्थिति नहीं दिखाई गई है, अपने आप में किसी भी तरह से अपराध की गंभीरता को कम नहीं करेगा।



23- अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों पर समग्र रूप से विचार करने के पश्चात्, मेरा यह सुविचारित मत है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के अंतर्गत अपीलकर्ता की दोषसिद्धि और उसके अंतर्गत दिया गया दंड उचित है और इसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। परिणामस्वरूप, यह अपील खारिज की जाती है।

सही/-

श्री दिलीप रावसाहेब देशमुख

न्यायाधीश

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

